शरद पवार का चीनी प्रेम अब भी बरकरार

शुगर निदेशालय को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय में लाने की कोशिश

आर.एस. राणा • नई दिल्ली

वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे शुगर निदेशालय को अब खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से हटाकर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के अधीन लाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे केंद्रीय कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री शरद पवार का 'चीनी प्रेम' माना जा रहा है। इस मामले की फाइल इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पास विचाराधीन है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार चाहते हैं कि शुगर निदेशालय, जो कि वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है, को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन लाया जाए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के अधीन है। इसे बदलने के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि चीनी उद्योग एक प्रसंस्करण उद्योग है इसलिए ऐसा किया जाए जबकि सच्चाई यह है कि शरद पवार किसी भी कीमत पर शुगर उद्योग पर अपना सीधा नियंत्रण कायम रखना चाहते हैं। शुगर निदेशालय वर्तमान में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले मंत्री प्रो. के वी थॉमस के अधीन है। इस मामले की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के पास गई हुई है तथा इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। शुगर निदेशालय का मंत्रालय बदलने का फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी. रंगराजन की अगुवाई में गठित विशेषज्ञ समिति ने चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश कर रखी है। वहीं, केंद्रीय खाद्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रो. के वी थॉमस भी चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने की कमेटी की सिफारिशों के पक्ष में हैं।